

Central Prohibition Committee

7126. SHRI YUVRAJ: Will the Minister of EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE be pleased to state:

(a) whether the Central Prohibition Committee has requested the State Governments to stop the sale of country liquor from 1st April during the current year, and

(b) whether the Committee has also requested that the sale of liquor near the educational institutions and religious places etc. should be banned and neither new licences for the sale of liquor should be issued nor old licences should be renewed, and if so, whether the laws will be duly amended with the view to enforce this policy successful and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (SHRI DHANNA SINGH GULSHAN): (a) No, Sir.

(b) Guidelines issued by the Government of India to the State Governments for implementation of prohibition include the following provision:— withdrawal of licences to shops:

(i) near industrial, irrigation and other projects.

(ii) on highways, residential areas, educational institutions, religious places and colonies of workers.

These guidelines were approved by the Central Prohibition Committee at its meeting held on 27 September 1978.

Enactment of legislation for prohibition and its enforcement are the responsibility of the State Governments.

पूर्वोत्तर क्षेत्र में पशुपालन विकास

7127. श्री हयाराम शायब :
श्री कुकन च :

क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के पूर्वोत्तर राज्यों में पशुपालन विभाग के विकास के सम्बन्ध में कोई जांच की है ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्र सरकार ने गत दो वर्षों में कितनी राशि की सहायता की ?

कृषि और सिंचाई मंत्री (श्री सुरजीत सिंह बरनाला) : (क) और (ख). देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पशुपालन विभाग के विकास के सम्बन्ध में कोई जांच नहीं की गई है। तथापि मध्यावधि योजना वार्षिक योजना पर विचार करते समय इस क्षेत्र में पशुपालन विकास की समीक्षा की गई थी।

(ग) एक विवरण सलग्न है।

विवरण

	राशि (लाख ₹)
1. कृषि और सिंचाई मन्त्रालय, कृषि विभाग की योजनाओं के जरिए सहायता	68.88
2. अनुसन्धान योजनाओं के लिए भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् से सहायता	19.43
3. गृह मन्त्रालय से उत्तर पूर्वी परिषद् को सहायता (दिसम्बर, 1978 तक)	123.45
4. आदिवासी उप-योजना के अन्तर्गत गृह मन्त्रालय से प्रथम, मणिपुर और ज़िपुरा क. सहायता	60.50
	(1978-79) †
† 1977-78 के दौरान पशुपालन और डेरी विकास सहित कृषि और सम्बन्ध क्षेत्रों को	293.65 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई थी।

Dam on Kalpana River

7128. SHRI MANORANJAN BHAKTA: Will the Minister of AGRICUL-